

राज्य का नाम	खरीफ, 94		रबी, 94-95	
	कुल ईसीए आबंटन	30.9.94 तक कुल ईसीए आबंटन संचयी उपलब्धता	30.9.95 तक संचयी उपलब्धता	
उड़ीसा	214.89	167.94	108.60	116.63
प० बंगाल	337.77	347.60	552.83	553.21
आसाम+एनई स्टेट्स	94.53	76.58	83.68	89.32
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.12	0.12
अखिल भारत	8381.14	8442.19	10109.26	10274.55

कपास की फसल में कीड़ा

491. श्री रामजीलाल: क्या कृषि मंत्री 8 दिसम्बर, 1995 को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न 1241 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपास की फसल के किन-किन कीड़ों के संबंध में कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है परन्तु फिर भी कपास की फसल उत्तरी भारत में कम होती जा रही है; और

(ख) क्या सरकार ने इस कीड़े से संबंधित कोई समिति गठित की है जिस पर किसी दवा का असर नहीं होता है, किसानों को होने वाले नुकसान को तुरन्त रोकने के लिए और जिसके संबंध में वैज्ञानिक अमेरिकन सुण्डी कह कर कोई ध्यान नहीं देते है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान): (क) कपास की फसल पर कई नाशी जीवों का आक्रमण होता है जिससे इस फसल की उपज कम हो सकती है। इनमें गुले वाले कीड़े (भुंग) भी शामिल हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने इन नाशी जीवों के नियंत्रण के लिए अनेक व्यापक अनुसंधान किए हैं और ठोस समेकित नाशी जीव प्रबन्ध विधियां विकसित की हैं। तथापि देश के उत्तरी राज्यों में हाल में कपास की उपज में कमी का कारण असमान तथा अधिक वर्षा और प्रतिकूल मौसम है। जब मौसम संबंधी विपरीत परिस्थितियां फसल में फूल आने और गुले बनने के समय होती हैं तो इनका और भी प्रतिकूल प्रभाव होता है।

(ख) सरकार ने सभी महत्वपूर्ण फसलों, जिसमें कपास की फसल भी शामिल है, में नाशी जीवों की

नियमित निगरानी के लिए नाशी जीव चौकसी दलों का गठन किया है, ताकि नाशी जीवों के नियंत्रण के लिए समय पर उपयुक्त उपाय अपनाये जा सकें। किसान-फ़ील्ड स्कूलों के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ताओं और किसानों को प्रदर्शन व प्रशिक्षण के द्वारा समेकित नाशी जीव प्रबन्ध का गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं ताकि कपास की फसल को समेकित नाशी जीव प्रबन्ध को अपनाया जा सके।

अमेरिकी गुल्लों के कीड़े (सुंडी) में कृत्रिम पाइरेथ्राइड के नाम से जाने जाने वाले रासायनिक नाशी जीव नाशियों के एक समूह के प्रतिरोधिता उत्पन्न हो गई है। इस समस्या के निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इन रसायनों के उपयोग को हतोत्साहित किया है और जैविक नियंत्रण एजेंटों तथा जैविक नाशी जीव नाशियों के उपयोग पर जोर देते हुए समेकित नाशी जीव प्रबन्ध की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है।

Newspaper Report on Controlled Drugs List

492. SHRI H. HANUMANTHAPPA:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item in 'Financial Express' of 11th February,

1996 captioned "DC&P may bring back five drugs on controlled list";

(b) if so, whether this step is being taken on the basis of abnormal increase of prices of medicines based on these drugs;

(c) the price of each formulation based on each drug during 1994 and the present price alongwith the percentage increase on each strength and pack;

(d) whether the prices of decontrolled medicines have gone up from 50 per cent to 400 per cent after the announcement of Price Control Order; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) Of the five bulk drugs mentioned in the news item, Metronidazole, Doxycycline and Pentazocine are already under price control under DPCO, 1995 however, in the cases of last two drugs, the bulk drug manufacturer has been granted exemption on the basis of developing process and technology through own R&D efforts in accordance with the provisions of DPCO, 1995. Nifadipine is not under price control under DPCO, 1995 nor it was so under DPCO, 1987. In case of Voveran the bulk drug concerned is Diclofenac which has gone out of price control under DPCO '95 and in this case it is observed that prices charged by various formulators are comparable. In this context it may be mentioned that Small Scale Units are exempt from price control, except for ceiling packs, and that all formulators of bulk drugs, which are not under price control, are free to determine their own prices. The Government would intervene only if prices charged are unreasonable and not justifiable.

Recognition to Kol Tribe as Scheduled Tribe

493. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kol tribe of Allahabad, Mirzapur and Sonobhadra district are recognised as Scheduled Tribe;

(b) whether it is also a fact that State Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have adopted different norms for recognition of this tribe;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether the Uttar Pradesh Government has sent any recommendation to the Centre regarding recognition of this tribe as Scheduled Tribe; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) No, Sir. However, the Kol community has been specified as a Scheduled Caste in relation to the State of Uttar Pradesh.

(b) and (c) According to the provisions of Articles 341 and 342 of the Constitution, the State Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are not empowered to confer on any community the status of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe. Such status can be accorded only by an Act of Parliament.

(d) Yes, Sir. The State Government of Uttar Pradesh have recommended that the Kol community in that State be recognised as a Scheduled Tribe instead of as a Scheduled Caste.

Joint venture in Mining with Australia

494. SHRI SARDA MOHANTY: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to establish joint venture with Australia in the field of mining;